International Research Journal of Humanities, Language and Literature
ISSN: (2394-1642)
Impact Factor 7.972 Volume 12, Issue 3, March 2025
Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
Website-www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

भारतीय राजनीति (राज्य) में धर्मनिरपेक्षता (पंथनिरपेक्षता) की आवश्यकता

डॉ0 मो0 इमरान खान
एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान
मुमताज़ पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ

भारत सदियों से अपनी सहिष्णुता, अनेकता में एकता, वसुधैवकुटुम्बकम के लिये जाना जाता है, आधुनिक राज्य में भी भारत अपनी बहुल्तावादी रूप बनाए रहा तभी तो भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन धर्मनिर्पेक्ष तथा आपसी भाई चारे के रूप में आगे बढ़ा।

धर्मनिर्पेक्षता एक आधुनिक शब्द है जिसका अर्थ है राज्य का कोई धर्म नही जो संत टॉमस एक्विना के धर्म प्रधान राजनीति के विचार से विभेद करते हुए चर्च (पोप) विरोधी राज्य के रूप में पाडुआ के मार्सिलियों के विचार के रूप में सामने आया। फलस्वरूप राष्ट्रीय राज्यों का पुनः उदय हुआ और धर्म व्यक्ति का निजी मामला बताया गया।

धर्म हिन्दी के धृत शब्द से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, हम अपने जीवन में जिन मानवीय मूल्यों तथा नैतिकता को धारण करते हैं, वही धर्म है, भारतीय परम्परा अपने नैतिक मूल्यों के कारण पहचानी गई भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने बहस–मुबाहिसों के बाद यह फैसला किया कि आजाद भारत अपनी विरासत के अनुरूप ही धर्मनिरपेक्ष राज्य रहे, वैसे वह चाहते तो भारत को धर्म सापेक्ष राज्य बना सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान बन चुका था।

अब भारत में धर्म निरपेक्षता का मॉडल कैसा हो युरोपीय या विशुद्ध भारतीय यह तय किया गया कि भारत राज्य का कोई धर्म (इस्लाम, सनातन, ईसाई, जैन, बौद्ध) न होगा। हाँ भारतियों का अपना व्यक्तिगत धर्म हो सकता है। उसको मानते हुए उसका प्रचार भी कर सकते हैं। किन्तु राज्य की कानून व्यवस्था राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को नुकसान पहुँचाए बगैर और राज्य भी अपने सेवा देते समय धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नही करेगा। किन्तु स्वतंत्रता के उपरान्त दूसरे दशक से एक बार फिर साम्प्रदायिक ताकतें उभरने लगी। जिससे भारतीय धमनिर्पेक्षता को खतरा महसूस होने लगा। दुर्भाग्य से सत्ताधारी दल ने साम्प्रदायिक ताकतों को खुश करने की कोशिश की वहीं विपक्षी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों ने इन्हीं ताकतों से सन् 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में परोक्ष रूप सहयोग किया। अल्पमत जनतादल की सरकार भाजपा व वामपंथी दलों के बाहरी समर्थन से बनी इस प्रकार सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों ने साम्प्रदायिक दलों के तुष्टीकरण तथा

उन्हें वैद्यता एवं सम्मान प्रदान करने का खेल खेलना जारी रखा, परिणामतः धर्मनिरपेक्ष लोगों की एक बड़ी संख्या यह महसूस करने लगी कि साम्प्रदायिक पार्टियों को सर्मथन देना गलत नही है, ऐसे नाजुक समय में बुद्धिजीवी भी समय की नजाकत को समझ न पाये, साम्प्रदायिक ताकते जहाँ जन सम्पर्क बढ़ाने में व्यस्त थीं, वहीं धर्मनिरपेक्ष नितियों के समर्थक सिर्फ गोष्ठियां ही करते रहे। इस तरह भारत के राजनीतिक दलों ने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की मजबूती से पैरवी न कर अपनी लाभ–हानि के आधार पर निर्णय किया। जैसा कि श्री जसवंत सिंह (पूर्व भाजपा सांसद) का मत है कि, धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकों में दह”ात फैला कर फिर उस दह”ात का शोषण करते हुए वोट खीचने का जारिया भर रह गई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि, धर्मनिरपेक्षता की नेहरू की परिकल्पना ऐसी नहीं रही होगी, जिस रूप में इसे आज लिया जा रहा है, आज इसका जो स्वरूप है, वह राष्ट्र के लिये घातक है, धर्मनिरपेक्षता आखिर शासन चलाने का सिद्धान्त भर नही है, यह तो अनोखा और कारगर सिद्धान्त है, इसे ऐसी मूर्ति नही बनाया जाना चाहिये, जिसे मन्दिर में स्थापित करके पूजा शुरू की जा सके, मगर हम यही कर रहे हैं। इस तरह जसवंस सिंह जी ने अहम सवाल उठाया है कि धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ नारा बना दिया गया है। जबकि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को यानि आपसी भाईचारा एवं सबका सम्मान आदि विचार समाज में मजबूती से लोगों को समझाया जाये तभी भारत राज्य एक मजबूत एवं विकसित हो सकता है।

आज भारतीय राजनीति में नए प्रतिमान बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बुरी हार और केन्द्र में तीन द”ाक बाद बहुमत की सरकार बनी और तीसरा कार्यकाल भी प्रारम्भ कर दिया है जिसका नारा है सबका साथ–सबका विकास और वि”वास भी। यह सरकार धर्मनिरपेक्षता के विचार को अलग नजरिये से देखती है। इसीलिए गत दो द”ाक से पंतनिरपेक्ष शब्द प्रयोग किया जा रहा है।

बाबरी मस्जिद रामजन्मभूमि के विवाद का उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय आ चुका है, जिसको सभी भारतवासियों ने माना, भारत में सौहार्द का वातावरण बना रहा है। उक्त निर्णय में यह भी कहा गया है कि धार्मिक स्थल 1991 का संसदीय अधिनियम अब किसी नए विवाद को जन्म नही देगा। किन्तु हम देखते हैं कि नित नए विवाद सामने आ रहे है। उम्मीद हैं कि उच्चतम न्यायालय में उक्त अधिनियम सम्बन्धित वाद का निर्णय जल्द ही आएगा। दूसरी तरफ राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी भी यह कह रहे हैं कि अब नए विवाद नही उठाए जाने चाहिए। भारतीय राज्य के सामने अन्य अनेक चुनौतियाँ हैं जिसमें सफल होने के लिए है आर्थिक विकास पर ध्यान देना होगा ऐसे में भारतीय राज्य धर्म निरपेक्षता (पंत निरपेक्षता) के मार्ग पर चलेगा तो सबका साथ, विकास, वि”वास और सम्मान सही अर्थ में व्यवहारिक होगा तभी भारतीय राज्य अपने उद्दे”यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ :–

1. विपिन चन्द्र – भारत का स्वतंत्रता संघर्ष
2. मधुपूर्णिमा कि”ावर – राजवाद की चाकरी में धर्म
3. मनोज सिंहा – समकालीन भारत
4. विपिन चन्द्र – आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता

5. आलोचना (त्रैमासिक) – भारतीय जनतंत्र का जायज़ा – 1